review the progress made in Hindi translation work with a view to determine whether in the context of the present work-load, the existing strenght of staff needs to be augmented.

Retrenchment of casual workers on Southern Railway

3454. SHRI MOHAMMAD ISMAIL : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) the number of casual workers employed under the Southern Railway ;

(b) the number of casual Workers recently retrenched from Southern Railway ;

(c) whether they have been served with valid retrenchment notices ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI HANUMANTHAIYA) : (a) 30808.

(b) 2724.

(c) Yes, wherever necessary.

(d) Does not arise.

12.05 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

ANTI-INDIAN RIOTS IN SOUTH NEPAL

SHRI B. R. SHUKLA (Bahraich) : I call the attention of the hon. Minister of External Affairs to the following matter of urgent public importance and I request that he may make a statement thereon :

"The reported recent anti-Indian riots in South Nepal resulting in about 1,000 Indians leaving Nepal for Purnea district of Bihar."

THE DEPUTY MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SURENDRA PAL SINGH) : Government have received reports that there have recently been riots in Gaurigani, District Jhapa, and in some other places in Mechi and Kosi Anchals in Nepal. The trouble started on June 10 when a clash took place between two rival groups of Pahari and Madhesia students, some of whom supported the Headmaster of the Gaurigani High School and others supported the Secretary of the High School.

Later, trouble spread when the Pahari students attacked some shops in the market, and were assisted by some Rais and Limbus from nearby villages. The Nepali police have indicated that they are making effort to bring the situation under control ; our Embassy in Kathmandu is in contact with the Government of Nepal.

Owing to the prevailing tension, a number of persons of Indian origin have taken shelter in Purnea district of Bihar. It is our expectation that normalcy will be restored and these people will return soon to their homes.

SHRI B. R. SHUKLA : This statement made on behalf of the Government is very meagre and sketchy because it has not indicated how many shops have been looted and how many Indians have been subjected to other types of harassment. It has merely contented itself with stating that some shops in the market were attacked. I want to know the result of this attack, whether the shops attacked belonged to persons of Indian origin or of Nepalese origin.

Secondly, I would like to know whether any arrest by the Nepal Government has been effected in this connection, whether the people responsible for this outbreak of riots against Indians have been taken to task and produced in a court of law.

Thirdly, it has also not been stated in this statement how many persons of Indian origin have actually fled from Nepalese territory and entered India, and the condition of the property left behind by them in Nepal. So, a fuller statement is expected from the Government.

Moreover, such an outbreak is not a new and isolated phenomenon in the history of Nepal. There have been periodical repeated outbreaks in which Indians have been subjected to harassment and have also been deprived of their property. Perhaps our policy of extreme liberalism and tolerance has been consistently mis-construed by the

neighbouring countries of India to mean that we are weak in dealing effectively with them. Therefore, I want a reassurance from the Government as to how normalcy would be affected because the riots started as early as June 10th and still they have not stopped. I want to know what steps are being taken to restore normalcy and how long it will take, and why our Ambassador in Kathmandu has not given an early report about these happenings.

SHRI SURENDRA PAL SINGH : This incident took place not very long ago, and it is a fact that we have not got all the details that we would like to have. We are in touch with our Embassy and have asked them to send details as quickly as possible

It is difficult for me to say how many shops were looted during the riots, but it is a fact that all the shops which were looted on that occasion belonged to people of Indian origin. It is difficult to say how many shops there were. As regards the number of persons who have crossed the Indian boundary, the number is round about 1300. Various figures are quoted from 500 to 1300 ; the maximum is about 1300, and they are mostly dependents of persons who have remained behind in Nepal. All of them have not come over. Some fearing further rioting, have sent their women and children ; the menfolk have remained in Nepal. In my opinion the hon Member has painted a dark and dismal picture and tried to make out as if the people of Indian origin in Nepal are not secure and some kind of a deliberate policy is being pursued against them. He has blown the problem out of all proportions. It is a very small incident. Such incidents, if I may say so, take place in every society and in it we should not try to read too much. The situation is under the control of the Nepalese authorities and our people have been in touch with them. They have been assured that the police authorities are taking vigorous action against the evil doers and they are sure to bring the situation under control very soon.

श्री के० एन० तिवारी (बेतिया) : अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय ने कहा कि हमने अम्बैसेडर का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है और वह नेपाल सरकार से बातचीत कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इसके सम्बन्ध में नेपाल सरकार का रिऐक्शन क्या है, और कब तक यह लोग वापस चले जायेंगे ?

दूसरी बात यह है कि इस घटना के पहले और भी घटनायें हो चुकी हैं। मैं जानना चाहता हूं कि उन घटनाओं के बाद कितने लोग वहां से आगे थे और वह लोग वापस चले गये या नहीं ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : मैं इस मामले के बारे में पहले ही कह चुका हूं कि जो हमारे काठमांडू में अम्बैसेडर हैं वह नेपाल सरकार से बात चीत कर रहे हैं, और नेपाल सरकार ने कहा है कि वह इस मामले को जल्दी काबू में ले आयेंगे और हम आशा करते हैं कि वहां कंडिशन्स जल्दी ही नार्मल हो जायेगी और जितने लोग वहां से डर की वजह से चले गये हैं वह सब वापस चले आयेंगे।

माननीय सदस्य ने जो दूसरे मामलों के बारे मे कहा वह सही है कि कुछ अर्से पहले कुछ लोग कंचनपुर इलाके से आ गये थे और वह वापस नहीं जा सके हैं। हमें नेपाल सरकार ने विश्वास दिलाया है कि उनके डाकुमेंट्स और दस्तावेज वगैरह देख रहे है और जब टाइटल डीड्स वगैरह वेरिफाई हो जायेंगे और यह मालूम हो जायेगा कि वह उन्हीं लोगों के हैं तब उनको वापस आने की इजाजत मिल जायेगी।

श्री एन० एन० पांडे (गोरखपुर) : अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से मंत्री महोदय ने जवाब दिया है, उसको देखते हुए मैं ऐसा समझता हूं कि उनको वस्तुस्थिति को जानने की और कोशिश करनी चाहिए।

नेपाल में जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, जिनको नेपाल वाले मध्य एशियाई कहते हैं, जिनकी 50 प्रतिशत से अधिक आबादी है, उनको 1961 से ही नेपाल गवर्नमेंट द्वारा बराबर हटाने की कोशिश की जा रही है। इसके सम्बन्ध में बहुत सी घटनायें हो चुकी हैं। मैं नेपाल के बहुत से जिलों का दौरा करके आया हूं। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि वहां की स्थिति क्या है भारतवासियों की, जिनको नेपाल गवर्नमेंट अब

[श्री एन० एन० पांडे]

एशियाई कहती है। इसलिए मंत्री महोदय को अपनी एम्बैसी के द्वारा और भी जानकारी वहां से प्राप्त करनी चाहिये।

यह पहली घटना नहीं है। बहुत सी ऐसी घटनायें नेपाल में पहले हो चुकी हैं। मैं उनके डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन मर्ज क्या है यह मैं मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर बन्दोबस्त चल रहा है और बन्दोबस्त में जो इंडियन ओरिजिन के लोग है उनसे कहा जा रहा है कि वह इस बात का प्रमाण लायें कि वह भारतवासी हैं या नेपाल के रहने वाले हैं। यदि भारतवासी प्रमाण-पत्र लेकर जमा करते हैं तो सारी फेमिली में से एक आदमी को वहां रहने दिया जाता है, बाकी लोगों से कहा जाता है कि आप भारत वापस जायें। वहां की असली कंडिशन क्या है यह मैं माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं। इस तरह से सारे भारतीय लोगों को वहा से हटाकर उनकी जगह जो गुरखा रिफ्यूजी हैं या पेंशनर हैं, उनको लाकर बसाया जा रहा है। एक बड़े पैमाने पर सारे तराई क्षेत्र मे ऐसी स्थिति पैदा की जा रही है कि वहां पर नेपालियों की मैजारिटी हो सके। 1961 तक वहां पर जिन जिन लोगों की मैजारिटी रही है उन पर नेपाली कांग्रेस का प्रभाव रहा है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 1961 मे वहां की जनता नेपाली कांग्रेस को हुकूमत में के आई, और हुकूमत में उनके आने के थोड़े दिन बाद भी वहां पर आंदोलन हुआ और वहां के लोगों ने अपने राइट्स मांगने शुरू किए तथा वहां की गवर्नमेंट को तोड़ा गया। वहां पंचायती राज कायम किया गया, और आजकल सारी नेपाली कांग्रेस के नेता, जो कि वहां की असली प्रतिनिधि सभा है और जिसकी जनता द्वारा चुनी हुई सरकार थी, श्री विश्वेश्वर प्रसाद कोईराला भारत में पड़े हुये हैं, सारी नेपाली कांग्रेस के नेता भारत में पड़े हुए हैं। वहां जनतन्त्र खत्म कर दिया गया है और जनतंत्र खत्म करके जितने उनके लोग हैं उनकी प्रापर्टी कंफिस्केट की जाती है और कहा जाता है कि यह मध्य एशियाई हैं, इंडियन ओरिजिन के हैं, इस लिए उन्हें निकाल दो। यह षड़यन्त्र चल रहा है, जिसकी तरफ मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय अपने इन्डियन डिप्लोमेट्स के द्वारा इस बात को जानने की कोशिश करे ताकि वह इसके सम्बन्ध में आगाह हो कि इसका क्या निराकरण है।

मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि आज वहां पर स्थिति वैसी ही हो रही है जैसी बंगला देश में हो रही है। मंत्री महोदय ने सब कुछ जानते हुए भी यह कहा कि मध्य एशियाई और नेपाली लोगों में झगड़ा हो गया, फसाद हो गया तथा मध्य एशियाई नेता, जो कि इस आन्दोलन को चला रहे हैं, वह अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहते है। जिन लोगों ने आन्दोलन किया, उनको मारा गया, उनको जान से मार डाला गया, इसको मंत्री महोदय को भूलना नहीं चाहिए। मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि जनकी स्थिति को मजबूत करने के लिए यह सरकार अपनी एम्बैसी के द्वारा क्या उपाय कर रही है?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मध्य एशियाइयों और पहाड़ियों के बीच जो मतभेद है, जो ताल्लुकात खराब हो रहे हैं उसके बारे मे हमें काफी तरह से मालूम है। यह मामला हाउस में पहले भी आ चुका है। यह सही है कि इस किस्म के छोटे मोटे वाक्यात होते रहते हैं, लेकिन जहां तक इस वाक्ये का सवाल है, जाँच पड़ताल से मालूम हुआ है कि इसका उस मामले से क्या सम्बन्ध नहीं है। यह झगड़ा एक स्कूल के मामले में एलेक्शन के वक्त शुरू हुआ, जैसे झगड़े हमारे यहां भी हो जाया करते हैं। दो ग्रुप्स थे स्टूडेंट्स के, वह आपस में लड़ने लगे। बदकिस्मती से यह सही है कि दोनो ग्रुप्स ऐसे थे एक मध्य एशिया वालों का था और एक पहाड़ियों का था। यह झगड़ा बढ़ गया और बढ़ते बढ़ते बाजार तक पहुंच गया। लेकिन मैं माननीय सदस्य की यह बात मानने के लिये तैयार हूं कि जहां तक मध्य एशिया वालों का सवाल है, इसमें शुबहा नहीं कि उनके रास्ते में बहुत सी दिक्कतें हैं और उन दिक्कतों

के सम्बन्ध में हमने वक्तन फवक्तन नेपाल सरकार से कहा है, जैसा कि हमारी ट्रीटी में भी कहा गया है, कि वह हमारे यहां के आदमियों को अपने यहां के आदमियों के बराबर स्तर पर रक्खें, और ऐसा उनको करना चाहिए। जैसे नेपाल के नागरिक हमारे यहां आते हैं तो उनको भी अख्त्यार वही होते हैं जैसे हमारे आदमियों के यहां पर हैं। इसमें कुछ कमी रही है और वह इसको नही कर पाये है उनके रास्ते में दिक्कतें है और कई बार हम उनकी नोटिस में यह बात लाये है। उनको विश्वास दिलाया है कि जहा तक हो सकेगा इन दिक्कतों को रफा करने की कोशिश होगी और उनकी मुसीबतो को दूर करने की कोशिश की जायेगी। हम आशा करते है कि वह ऐसा करेंगे।

बाकी इसके बारे मे ज्यादा कहना उचित नही है क्योंकि वह वही के नागरिक है, वही के रहने वाले है और नेपाल स्वतन्त्र देश है। वह अपनी पालिसी अपने आप बनाते है, इसलिए ज्यादा कुछ कहना ठीक नही है। लेकिन अपना फर्ज पूरा कर रहे है और इन सब बातो को हम उनके नोटिस मे लाते रहते है।

श्री कमल मिश्र मधुकर (केसरिया). पहली बात मै यह कहना चाहता हूं कि नेपाल मे चाहे किंग महेन्द्र का राज्य हो या नेपाली कांग्रेस का इससे हमारा सम्बन्ध नही है और उनके देश मे कैसी व्यवस्था हो इससे भी हमें मतलब नहीं है। मै चाहूंगा कि हमारे और नेपाल के बीच मे अच्छे सम्बन्ध हों क्योंकि वह हमारा निकट का पड़ोसी देश है। ऐसी कोई कार्यवाही नही होनी चाहिए जिससे हमारे आपस के सम्बन्धों में तनाव पैदा हो। लेकिन आज अपने देश की हालत ऐसी हो गई है कि जो भी इंडियन ओरिजिन के लोग है, चाहे सीलोन हो, चाहे अफ्रीका हो या चाहे कहीं और हो, सब जगह पर उनकी अवस्था बहुत खराब है। सब जगहों पर उनको शरणार्थियों की तरह ट्रीट किया जाता है। ऐसी अवस्था हो गई है कि जो लोग बाहर रहते हैं, मालूम होता है जैसे वह लावारिस हों। क्या सरकार इस बात पर गौर कर रही है कि ऐसी व्यवस्था की जाय उन सरकारों के साथ कि जहां पर भी भारतीय लोग विदेशों मे रहते हैं उनको वहां पर वह सम्मान के साथ रक्खें और लावारिस की तरह न रहें? साथ ही क्या आप ने इस बात का कोई प्रयत्न किया है कि कोई डेडलाइन बनायें कि इतने दिनों के अन्दर जो शरणार्थी आ गये हैं, चाहे वह बंगला देश के शरणार्थी हों या नेपाल से आये शरणार्थी हों वह लौट जायेंगे क्योंकि उनके न जाने से हमको दिक्कत पड़ेगी? मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय सदन में यह स्पष्ट करे कि क्या वह इन शरणार्थियों को नेपाल भेजने की कोई व्यवस्था कर रहे हैं ताकि हमें विश्वास हो कि यह शरणार्थी हमारे ऊपर बोझ बन कर नही रहेगे?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : माननीय सदस्य की इस भावना का स्वागत करता हूं कि हमारे ताल्लुकात नेपाल से अच्छे रहने चाहिएं और हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए और न ही कोई ऐसी बात कहनी चाहिए जिससे हमारे ताल्लुकात किसी से खराब हों।

जहा तक इस समस्या का सम्बन्ध है भारतीयों की समस्या तब तक हल नही होगी जब तक हमारे मुल्क के आदमी जहां भी जाते हैं या जहां जाकर रहते हैं वे वहीं के पूरे नागरिक न बन जाए और उस मुल्क के लोगों में पूरी तरह घुल मिल न जायें। जब तक वे अपनी कल्चरल टाइज या रिलिजस या दूसरी किस्म की टाइज दूसरे देश से रखेंगे उस वक्त तक स्वभावत. उनको शुबहे की निगाह से देखा जायगा। जहां जहां जाकर वे बस गये हैं उनको कोशिश करनी चाहिए कि वहां के जीवन मे घुल मिल जाएं, वहां के नागरिक बन जाएं ताकि वहां के जो इन्डिजिनस आदमी है उन्हें किसी किस्म की शिकायत न हो कि ये हमारी लाइफ के पार्ट एण्ड पार्सल नही है।

MR. SPEAKER : Papers to be laid.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur) : Sir, may I request you to ask the Foreign Minister to make a statement on the statement of President Yahya Khan accusing India? Yesterday we discussed it. President Yahya Khan has made such a nasty statement. He has said that the Awami League will not be allowed to have any power. The minister should make a statement on this.

MR. SPEAKER : It will be conveyed to him.

12.20 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

ANNUAL REPORT ETC. OF THE KHADI AND VILLAGE INDUSTRIES COMMISSION AND ANNUAL REPORT OF THE I. S I, FOR 1969-70

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) । मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :

(1) (एक) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 24 की उप धारा (3) के अन्तर्गत खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग, बम्बई के वर्ष 1969-70 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति तथा एक सांख्यिकीय विवरण [*Placed in Library. See* No. LT—546/71]

(दो) उपर्युक्त दस्तावेजों के अंग्रेजी संस्करण के साथ हिन्दी संस्करण सभा-पटल पर न रखे जा सकने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । [*Placed in Library. See* No. LT—547/71.]

(2) भारतीय मानक संस्था के वर्ष 1969-70 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति । [*Placed in Library. See* No. 553/71.]

2.21 hrs.

FINANCIAL COMMITTEES—1970-71 (A REVIEW)

SECRETARY : Sir, I lay on the Table a copy of the "Financial Committees, 1970-71 (A Review)".

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

SECRETARY : Sir, I have to report the following message received from the Secretary of Rajya Sabha :—

"In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha, at its sitting held on the 25th June, 1971 agreed without any amendment to the maintenance of Internal Security Bill, 1971, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 18th June, 1971."

DEMANDS FOR GRANTS*, 1971-72— *Contd.*

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

MR. SPEAKER : The House will now take up discussion and voting on Demand Nos. 90 to 94 144 and 145 relating to the Ministry of Communications for which 4 hours have been allotted.

Hon. Members present in the House who are desirous of moving their cut motions may send slips to the Table within 15 minutes indicating the serial numbers of the cut motions they would like to move.

Shri Rattanlal Brahman. This is very interesting. He wants to speak in Nepali. So far as our own languages are concerned, we are allowing them. Now, I put it to the House whether he should be allowed to speak in Nepali. I am not going to take up the responsibility for it. Tommorrow some member may want to speak in French or in Spanish.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur) : A Bill was moved in this House by Dr. Maitreyi Bose that Nepali should be included in the Eighth Schedule of the Constitution. That Bill was rejected. Though she was a Bengali, she was elected from Darjeeling. Now, Shri Rattanlal Brahman has been elected from Darjeeling. He can speak only in Nepali. The question is whether an Indian citizen elected from Darjeeling, knowing only Nepali, should be allowed to speak in that language or not in this House.

*Moved with the recommendation of the President.